हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

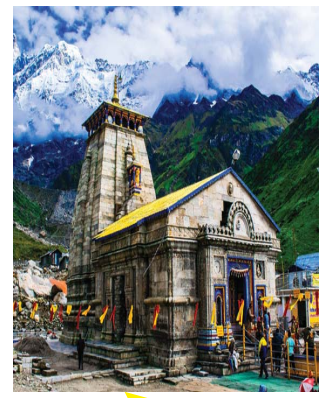

वर्ष:5 अंक:51 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, बुधवार, 25 फरवरी 2026

'सेवा तीर्थ' में पहली बार बैठा मोदी मंत्रिमंडल, नये कार्यालय को बताया देश के नवनिर्माण की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाल्गुन मास की शुक्ल अष्ठमी, मंगलवार को पहली बार यहां नवनिर्मित प्रधानमंत्री कार्यालय भवन 'सेवा तीर्थ' में अपनी पहली बैठक में 'सेवा संकल्प' प्रस्ताव पारित किया और इसे भारत की विकास यात्रा में एक नया आरंभ बताया।

इस प्रस्ताव में पिछ्ले एक दशक की उपलब्धियों और सुधारों को गिनाते हुए संकल्प व्यक्त किया गया है कि यह सरकार सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए भारत को निकट भविष्य में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करेगी। प्रस्ताव में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति मंत्रिमंडल की प्रतिबद्धता और समर्पण भी व्यक्त किया गया है।

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ' सेवा संकल्प' में कहा गया है, ' आज युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत् 1947, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष..अष्टमी के दिन...24 फरवरी, 2026 को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में, नए प्रधानमंत्री कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ऐतिहासिक प्रथम बैठक आयोजित हो रही है। '

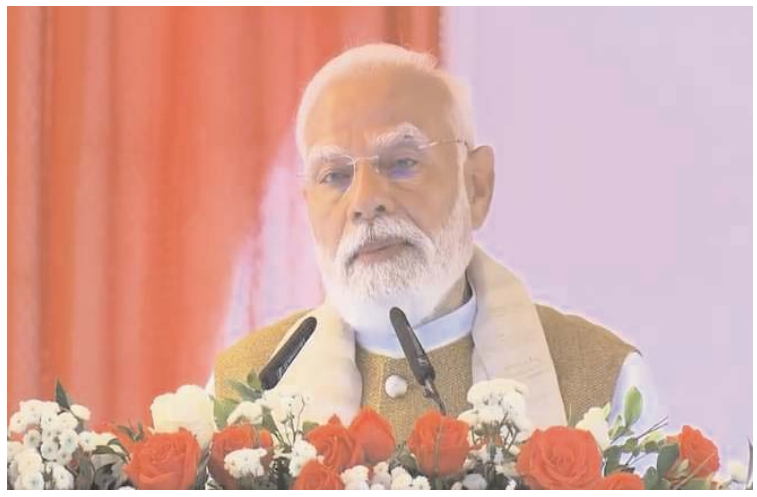

नये भवन को नये भारत के निर्माण की अभिव्यक्ति बताते हुए प्रस्ताव में कहा गया है, ' यह बैठक एवं यह भवन नए भारत के नवनिर्माण की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। इस

शुभारंभ के साथ ही हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं, जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में इतने दशकों तक सरकारों ने विरासत को संभाला और भविष्य के सपने देखे। हमने एक ऐसे भारत के सपने देखे, जिसकी सोच स्वदेशी हो, स्वरूप आधुनिक हो, और सामर्थ्य अनंत हो। आज यह सेवातीर्थ उसी संकल्पना का वह मूर्तिमान अवतार है जो लोकतन्त्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को बढ़ाएगा। '

नये प्रधानमंत्री कार्यालय के स्थान के अंग्रेजों के राज के दौर के बैरक वाले इतिहास को याद करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है, ' आज इस अवसर पर इस स्थान के इतिहास को भी स्मरण कर रहे हैं। 'सेवा तीर्थ' उन अस्थायी बैरकों के स्थान पर बना है, जो ब्रिटिश काल के थे। उस स्थान पर राष्ट्र संचालन के सक्रिय संस्थान का निर्माण नये भारत के कायाकल्प का भी प्रतीक है। '

प्रस्ताव में आगे कहा गया है, 'गुलामी के कालखंड से पहले भारत की पहचान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में होती थी जो एक ओर अपनी भौतिक भव्यता के लिए भी जाना जाता था, और दूसरी ओर अपने मानवीय मूल्यों के लिए। सेवातीर्थ की संकल्पना इन दोनों ही आदर्शों से मिलकर बनी है। कर्तव्य, सेवा और समर्पण की त्रिवेणी से यह कार्यस्थल एक तीर्थ की भांति पवित्र हो, यह इसकी मूलभावना है। '

इसमें कहा गया है, 'सेवा तीर्थ' में हो रही इस पहली बैठक के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प दोहराता है कि यहां लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के प्रति सेवा-भाव से प्रेरित होगा और राष्ट्र-निर्माण के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा होगा।

भारत के संविधान को सरकार की नैतिक प्रतिबद्धता बताते हुए प्रस्ताव में कहा गया है, ' हमारे लिए संवैधानिक मूल्य उस नैतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति हैं, जो शासन को नागरिक की गरिमा, समानता और न्याय से जोड़ती है। 'सेवा तीर्थ' की कार्य-संस्कृति इसी आत्मा से संचालित होगी, जहां हर नीति संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगी और हर निर्णय देशवासियों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होगा। '

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह संकल्प दोहराया - ' इस परिसर में लिया गया प्रत्येक निर्णय 'नागरिक देवो भव' की भावना से प्रेरित होगा। यह स्थान सत्ता के प्रदर्शन का नहीं, वरन् प्रत्येक भारतवासी के सशक्तिकरण का केंद्र बनेगा। सेवा तीर्थ' से संचालित शासन का हर प्रयास देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने की भावना से जुड़ा रहेगा। हम ये दोहराते हैं कि हम अपनी परिकल्पना के मुताबिक शासन के उस मॉडल को और मजबूती देंगे, जो पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक की संवेदनाओं के प्रति सजग हो। '

इसमें कहा गया है, ' 'सेवा तीर्थ' उस गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर (शासन कार्य की उस अवसंरचना) की आवश्यकता का उत्तर है, जो जड़ता की जगह गतिशीलता को, उदासीनता की जगह निष्ठा को और संदेह की जगह समाधान को बढ़ावा देता है।

इसी सोच के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते वर्षों में लिये गये निर्णयों ने शासन के उद्देश्य को नयी स्पष्टता दी है। करोड़ों नागरिकों के जीवन में आये बदलाव ने शासन के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत किया है। मोदी सरकार की एक दशक की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है, ' बीते एक दशक में 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालकर देश ने असंभव समझे जाने वाले काम को संभव करके दिखाया है। ऐसे अनेक कीर्तिमानों के पीछे सरकार की दूरगामी सोच, व्यापक परिकल्पना और अथक परिश्रम रहा है। आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने का गौरव देश ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भुखमरी के अभिशाप का अंत किया गया है।

एक नजर

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के माध्यम से उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। याचिका पर शीघ्र सुनवाई होने की संभावना है। गौरतलब है कि तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत जिला अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर अपर जिला एवं

सत्र न्यायाधीश (रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी थाने की पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के अनुपालन में झूंसी थाना पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी तथा दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 5रु 6, 3, 4(2), 16 और 17 के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है।

केरल का नाम 'केरलम्' करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली। मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम् करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 'सेवातीर्थ' में मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई पहली बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्चिनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के बाद से ही केरल के नाम को बदलने की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति 'केरल नाम परिवर्तन विधेयक, 2026' के मसौदे को केरल विधानसभा की स्वीकृति के लिए भेजेंगी। संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत राष्ट्रपति इस विधेयक पर केरल विधानसभा का मत प्राप्त करेंगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए बस्तर और अन्य पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, डिजिटल संपर्क और रोजगार के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में संकल्प थीम पर यह बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्ताव के मुताबिक सरकार ने इस वर्ष कुल व्यय 1.72 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है, जिसमें राजस्व व्यय 1.45 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़ रुपए रखा गया है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को गति मिलेगी, जिससे प्रदेश में विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी। बजट में पूंजी निवेश के लिए केंद्र से मिलने वाली विशेष सहायता को 4,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,500 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे बड़े बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.87 प्रतिशत पर नियंत्रित रखा गया है, जो संतुलित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है और राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत देता है। छत्तीसगढ़ के बजट में सामाजिक क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए कुल व्यय का 40 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए 36 फीसदी और प्रशासनिक एवं सामान्य सेवाओं के लिए 24 फीसदी राशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14,300

करोड़ रुपए का विशेष ग्रीन बजट का भी प्रावधान किया गया है।

बजट में सरगुजा, बस्तर और अन्य पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को केंद्र में रखा गया है। बस्तर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे अत्यंत संवेदनशील इलाकों में दो 'एजुकेशन सिटी' स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। खेल और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं।

बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहलों के लिए बजट में संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिल सके और क्षेत्र की सकारात्मक पहचान मजबूत हो। इसके साथ ही बस्तर फाइटर्स के 1500 नवीन पदों का सृजन किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत जगदलपुर में सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में डॉक्टरों की विशेष भर्ती की जाएगी, ताकि दूरस्थ इलाकों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार अपने ही क्षेत्र में मिल सके। सिंचाई क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए इंद्रावती नदी पर लगभग 2024 करोड़ रुपये की लागत से बैराज निर्माण की योजना घोषित की गई है। इससे बस्तर क्षेत्र में लगभग 32 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने का अनुमान है।

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने महिलाओं के नाम से संपत्ति क्रय पर लगने वाले पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 'रानी दुर्गावती योजना' शुरू की जाएगी, जिसके तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 'मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना' लागू की जाएगी, वहीं उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 250 महतारी सदनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। बजट में 'कृषक उन्नति योजना' के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता और कृषि विकास को गति मिलेगी।

डीएम मयूर दीक्षित के निर्देशों पर अतिक्रमण अभियान, सामान जब्त

पथ प्रवाह, हरिद्वार

जनपद में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर मंगलवार को नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान के नेतृत्व में कनखल क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान झण्डा चौक से बंगाली चौक और सतीघाट तक सड़क एवं फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया।

प्रशासन द्वारा चलाए गए इस अभियान में सड़क और फुटपाथ पर दुकानों के बाहर रखे सामान, रेहड़ी-ठेलियों और अन्य अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। मौके पर मौजूद प्रशासनिक टीम ने अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करते हुए भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी।

नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने बताया कि कनखल झण्डा चौक और आसपास के बाजारों में दुकानदारों द्वारा सड़क और फुटपाथ पर सामान रखने से यातायात

प्रभावित हो रहा था और आम नागरिकों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह अभियान चलाया। उन्होंने व्यापार संघ के पदाधिकारियों से भी अपील की कि वे दुकानदारों को निर्देशित करें कि दुकान के बाहर रखा गया सामान तुरंत हटा लें। यदि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सामान जब्ती के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पुलिस विभाग, नगर निगम हरिद्वार और लोक निर्माण विभाग को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जहां-जहां से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां दोबारा अवैध कब्जा न होने दिया जाए। यदि पुनः अतिक्रमण पाया गया तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सहायक नगर आयुक्त श्याम सुन्दर और नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में सुचारु यातायात और नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

एक नजर

कनखल में 10 मकान मालिकों पर 1 लाख के कोर्ट चालान, 60 सत्यापन

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर के निर्देशानुसार जनपद में बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों, कबाड़ियों और घरेलू नौकरों के सत्यापन हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कनखल पुलिस ने सघन सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान अलग-अलग टीमों का गठन कर कृष्णा नगर समेत विभिन्न क्षेत्रों में किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। पुलिस टीमों ने मौके पर कुल 60 व्यक्तियों का सत्यापन कराया। जांच के दौरान बिना सत्यापन के किरायेदार, घरेलू नौकर और बाहरी व्यक्तियों को रखने वाले 10 मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 83 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर 10,000 के हिसाब से कुल 1,00,000 के कोर्ट चालान किए गए। संबंधित रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जा रही है, जहां से जुर्माने की वसूली की जाएगी। इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान 15 व्यक्तियों के विरुद्ध 81 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 250-250 के चालान किए गए, जिससे कुल 3,750 की धनराशि वसूल की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने मकान मालिकों को निर्देशित किया कि वे अपने किरायेदारों, घरेलू नौकरों एवं बाहरी व्यक्तियों का शीघ्र सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही किरायेदारों, घरेलू नौकरों और फड़-ठेली संचालकों को भी समय रहते अपना सत्यापन कराने के लिए जागरूक किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में वरिष्ठ उपनिरीक्षक सतेन्द्र भण्डारी, अपर उपनिरीक्षक मुकेश धीमान, कांस्टेबल कुलदीप प्रसाद, कांस्टेबल गजेंद्र तोमर एवं महिला कांस्टेबल सुमन राणा शामिल रहे।

विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगेहाथों दबोचा जीएसटी कार्यालय में डाटा क्लर्क

पथ प्रवाह, हरिद्वार। विजिलेंस की टीम ने राज्य कर विभाग में तैनात एक डाटा क्लर्क को रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी क्लर्क पर वैट टैक्स प्रकरण निपटाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद सतर्कता अधिष्ठान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता ने सतर्कता अधिष्ठान को दी तहरीर में बताया कि उसकी हिमांशी पैकेजिंग इंडस्ट्री वर्ष 2021 में बंद हो चुकी है। जीएसटी लागू होने से पूर्व वर्ष 2017 के अंतिम तीन महीनों के वैट टैक्स निपटान के संबंध में विभाग द्वारा 1,76,000 की देनदारी बताई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस प्रकरण को निपटाने के एवज में राज्य कर कार्यालय में तैनात डाटा क्लर्क प्रमोद सेमवाल ने कथित तौर पर 1,20,000 नगद की मांग की और राशि को किस्तों

में देने के लिए कहा। जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान प्रमोद सेमवाल पुत्र शिव शरण सेमवाल, निवासी सिद्धार्थ एन्क्लेव, द्वारिका विहार, निकट फुटबॉल ग्राउंड, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार के रूप में हुई है।

कनखल पुलिस ने दिखाई सख्ती, 14 हुड़दंगियों को हवालात

पथ प्रवाह, हरिद्वार

कनखल कोतवाली क्षेत्र के जगजीतपुर स्थित सगरावाला मोहल्ले में नशे के अवैध कारोबार के विरोध को लेकर जमकर हंगामा हो गया। मोहल्लावासियों द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपित महिला ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद सभी ने मिलकर स्थानीय लोगों के साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज करते हुए क्षेत्र में उपद्रव मचा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला सहित कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है।

सूचना मिलते ही प्रभारी चौकी जगजीतपुर सुधांशु कौशिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पाया गया कि 14 व्यक्ति सड़क पर खड़े होकर हो-हल्ला, गाली-गलौज और झगड़ा कर रहे थे, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और यातायात भी बाधित हो गया। पुलिस ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके नहीं मानने पर शांति

व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी 14 आरोपितों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत कारण बताते हुए हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपितों में मौहम्मद मुन्ना निवासी अहबाबनगर ज्वालापुर, शंकर तोमर निवासी लाल मंदिर कॉलोनी ज्वालापुर, दीपक कोहरी निवासी ब्रह्मपुरी, मोहम्मद छोटा निवासी घोसियान ज्वालापुर, दीपक राजपूत निवासी हनुमानगढ़ी कनखल, सौरभ निवासी ब्रह्मपुरी, सूरज आर्या निवासी गणपतिधाम राजागार्डन, विजय चौहान निवासी ब्रह्मपुरी, विकास कुमार निवासी सतीकुंड सर्वप्रिय बिहार, सुमित निवासी कृष्णानगर, अमन सैनी निवासी डिवाइन लाइट स्कूल के पास, आशीष निवासी छतरीवाला कुआं जगजीतपुर, गोपी चौहान निवासी जगजीतपुर तथा एक महिला निवासी सगरावाला जगजीतपुर शामिल हैं।

पुलिस टीम

उपनिरीक्षक सुधांशु कौशिक, अपर उपनिरीक्षक ललित मोहन, कांस्टेबल प्रलव चौहान, कांस्टेबल रघुबीर सिंह और महिला कांस्टेबल रेखा शर्मा शामिल रहे।

कुम्भ मेला 2027: श्रीमहंत हरि गिरि महाराज हरिद्वार पहुंचे, मेला प्रशासन की बैठक में लेंगे भाग

पथ प्रवाह, हरिद्वार

हरिद्वार में वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुम्भ मेले की तैयारियों को लेकर अखाड़ों और मेला प्रशासन के बीच समन्वय प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमहंत हरि गिरि महाराज नासिक से हरिद्वार पहुंच गए हैं। उनके साथ सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर, जूना अखाड़ा के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता एवं दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्रीमहंत नारायण गिरि महाराज भी मौजूद रहे।

श्रीमहंत हरि गिरि महाराज बुधवार को कुम्भ मेला अधिकारी द्वारा अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं, सुविधाओं और आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मेला प्रशासन द्वारा मेले को ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अखाड़ों के संतों और प्रतिनिधियों से सुझाव

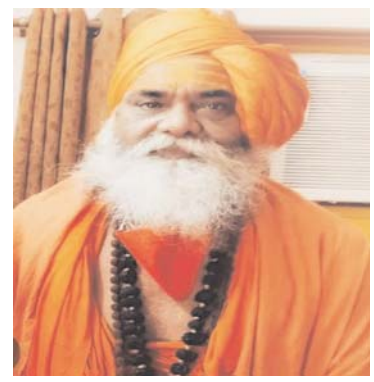

भी लिए जाएंगे, जिनके आधार पर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। श्रीमहंत नारायण गिरि महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार में वर्ष 2027 का कुम्भ मेला 14 जनवरी 2027 को मकर संक्रांति के पावन पर्व से प्रारंभ होगा और 20 अप्रैल 2027 को चैत्र पूर्णिमा तक आयोजित किया जाएगा। लगभग 97 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि कुम्भ मेले का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2027 को मकर संक्रांति पर होगा। इसके अलावा मेले के दौरान कुल 10 प्रमुख स्नान तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें मौनी अमावस्या (6 फरवरी), बसंत पंचमी (11 फरवरी), माघ पूर्णिमा (20 फरवरी), महाशिवरात्रि अमृत स्नान (6 मार्च), सोमवती अमावस्या अमृत स्नान (8 मार्च), नव संवत्सर (7 अप्रैल), रामनवमी (15 अप्रैल), बैशाखी शाही स्नान (14 अप्रैल) और चैत्र पूर्णिमा (20 अप्रैल) प्रमुख हैं।

कुम्भ मेला अधिकारी द्वारा अखाड़ों के साथ आयोजित यह बैठक मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने और संत समाज के सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मेला प्रशासन और संत समाज के समन्वय से कुम्भ मेला-2027 को भव्य, सुरक्षित और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है।

हुड़दंग करने वाले तीन आरोपियों पर कार्रवाई

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

सिडकुल थाना क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को सड़क पर सरेआम पर हो हल्ला व हुड़दंग बाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनकी हरकतों से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कुछ लोगों द्वारा उक्त व्यक्तियों का विरोध भी किया जा रहा था, राहगीरों में आम जन में काफी रोश व्याप्त था। मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा पहुंचकर उसको काफी समझाया बुझाया गया किंतु नहीं माने उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170 ब्नहस्स् के तहत कार्यवाई की गई। आरोपियो के नाम हर्षित पुत्र हरभजन सिंह निवासी ऐल्पस कालोनी हेत्तमपुर थाना सिडकुल हरिद्वार, विवेक नेगी पुत्र स्व0 गुमान सिंह नेगी निवासी ग्राम कोटा किन्दा यमकेश्वर ब्लाक थाना

यमकेश्वर जिला पौडी गढवाल हाल ज्ञानलोक कालोनी नवोदय नगर थाना सिडकुल हरिद्वार और रहीम पुत्र शहजाद निवासी मस्जिद के पास रोशनाद थाना सिडकुल हरिद्वार है।

कुम्भ मेला 2027: स्थायी विकास कार्य 31 अक्टूबर तक पूरे करने के निर्देश

अपर मेलाधिकारी दयानंद ने निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण

पथ प्रवाह, हरिद्वार

आगामी कुम्भ मेला-2027 के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर मेला प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत स्थायी विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मेला प्रशासन ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत सभी स्थायी निर्माण कार्य हर हाल में 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण किए जाएं।

मेलाधिकारी सोनिका के निर्देशन में विभिन्न निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नामित अधिकारी लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि सभी परियोजनाएं निर्धारित तकनीकी मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप समय पर पूरी हो सकें। मेला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी को गंभीरता

से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

इसी क्रम में अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कुम्भ मेला-2027 के अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभियंताओं को निर्देशित किया कि सभी कार्यों में तेजी लाई जाए तथा निर्माण सामग्री की नियमित जांच के साथ गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रत्येक परियोजना की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से मेला कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

अपर मेलाधिकारी ने धनौरी-सिडकुल लिंक मार्ग पर पथरी रौ नदी और पुरानी गंग नहर पर स्वीकृत पुल निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने नींव और पाइलिंग कार्य की तैयारियों का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह पुल कुम्भ मेला अवधि में यातायात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसके अलावा बहादराबाद विकासखंड में धनौरी-सिडकुल मोटर मार्ग के हॉटमिक्स डामरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। लगभग 8.4 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण कार्य में क्षतिग्रस्त हिस्सों को प्राथमिकता से ठीक करने और उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि सड़क लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ बनी रहे। अपर मेलाधिकारी ने रोशनाबाद स्थित निर्माणाधीन औषधि भंडारण कक्ष का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्माण सामग्री की नियमित सैंपलिंग और थर्ड पार्टी गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस आधुनिक वेयरहाउस में दवाओं के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड चेन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ?251.98 लाख की लागत से इस औषधि भंडारण परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने से कुम्भ मेला अवधि के दौरान ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी स्वास्थ्य विभाग को दवाओं और चिकित्सा सामग्री के सुरक्षित भंडारण और वितरण में महत्वपूर्ण सुविधा प्राप्त होगी।

निरीक्षण के दौरान कुम्भ मेला के तकनीकी सेल के अधिशासी अभियंता प्रवीन कुमार सहित संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता मौजूद रहे।

सिडकुल की जर्जर सड़कें बनी उद्योग और हजारों श्रमिकों की समस्या

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार स्थित स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड (SIDCUL) के IP-2 औद्योगिक क्षेत्र में बदहाल सड़कें उद्योगों और हजारों श्रमिकों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन गई हैं। क्षेत्र में संचालित 30 से 40 औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत करीब 25 से 30 हजार कर्मचारियों को प्रतिदिन आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जिससे न केवल कर्मचारियों की उपस्थिति प्रभावित होती है, बल्कि उत्पादन पर भी सीधा असर पड़ता है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि यह औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड सरकार को भारी राजस्व प्रदान करता है, इसके बावजूद यहां की बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

बरसात में पैदल चलना भी मुश्किल

उद्योग से जुड़े देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि डांसो चौक से शिवम ऑटो तक सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है। बरसात के दिनों में जगह-जगह गहरे गड्ढे बन जाते हैं और कई स्थानों पर चार फीट तक पानी भर जाता है। ऐसे में पैदल चलना भी

मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 20 से 25 हजार श्रमिक इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन सड़क और फुटपाथ दोनों ही उपयोग के योग्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि खराब सड़क और जलभराव के कारण कर्मचारियों की अनुपस्थिति बढ़ जाती है, जिससे उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होता है। साथ ही, क्षेत्र में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और पुलिस गश्त न होने के कारण महिलाओं की सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी हुई है। कई बार छेड़खानी और विवाद की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

औद्योगिक क्षेत्र की जीवनरेखा

युद्धवीर सिंह रावत ने इस सड़क को पूरे औद्योगिक क्षेत्र की जीवनरेखा बताते हुए कहा कि प्रतिदिन लगभग 20 हजार लोग रोजगार के लिए इसी मार्ग से आते-जाते हैं। क्षेत्र में स्थित स्कूलों के बच्चे, स्थानीय दुकानदार, होटल संचालक और आसपास के ग्रामीण भी इसी सड़क पर निर्भर हैं। उन्होंने बताया कि भारी वाहनों की आवाजाही के कारण खराब सड़क और अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है। कई बार खराब सड़क के कारण माल को भी नुकसान पहुंचता है। क्षेत्र की कई कंपनियां निर्यात से जुड़ी हैं, ऐसे में विदेशी ग्राहक भी यहां आते हैं और सड़क की बदहाल स्थिति देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जिससे क्षेत्र की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

श्रमिकों का पलायन बढ़ा

उद्योग प्रतिनिधि अंकुर दुबे ने बताया कि वर्ष 2008 में उद्योग स्थापित होने के बाद से सड़क का समुचित सुधार नहीं किया गया। खराब सड़क और सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण

श्रमिकों का पलायन भी बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों से नियमित परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे कर्मचारियों को समय पर कार्यस्थल पहुंचने में कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 35 से 40 कंपनियां संचालित हैं, जहां करीब 25 से 30 हजार श्रमिक कार्यरत हैं। सड़क की बदहाली का सीधा असर उद्योगों की उत्पादन क्षमता और कार्यप्रणाली पर पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी

स्थानीय निवासी लोकेन्द्र राठी ने बताया कि इस सड़क का कभी भी सही तरीके से निर्माण नहीं कराया गया। कई बार शिकायत करने के बावजूद केवल आश्वासन ही मिला है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रमिकों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थायी समाधान की मांग तेज

उद्योग प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क का पुनर्निर्माण, जल निकासी की उचित व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

उनका कहना है कि यह सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो इसका व्यापक असर उद्योगों, रोजगार और क्षेत्र के आर्थिक विकास पर पड़ सकता है।

तांत्रिक की हरकतों से परेशान अपार्टमेंटवासी, पुलिस ने किया चालान

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कनखल थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तम बिहार स्थित एक अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। आरोप है कि उक्त व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करते हुए अपार्टमेंट में तेज आवाज में भजन-कीर्तन और टीवी चलाकर शोरगुल करता था, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और आसपास के लोग परेशान थे। 23 फरवरी को थाना कनखल पुलिस को सूचना मिली कि पुरुषोत्तम बिहार स्थित अपार्टमेंट में रहने वाला एक व्यक्ति तांत्रिक विद्या के नाम पर शोरगुल करता है और आसपास के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। बताया गया कि आरोपी देर रात तक तेज आवाज में टीवी पर भजन-कीर्तन चलाता था, जिससे अपार्टमेंट में रहने वाले बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने में कठिनाई हो रही थी। स्थानीय लोगों ने कई बार आरोपी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और उल्टा गाली-गलौज कर झगड़ा करने लगा। स्थिति बिगड़ने पर अपार्टमेंटवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को समझाने का प्रयास

किया, लेकिन उसके नहीं मानने पर पुलिस ने उसे अंततः हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत कार्रवाई करते हुए आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार हिरासत में लिया गया आरोपी सत्य प्रकाश तिवारी पुत्र श्रीकांत तिवारी, निवासी पुरुषोत्तम बिहार, थाना कनखल, हरिद्वार है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक धनराम शर्मा, कांस्टेबल संजू सैनी और कांस्टेबल अरविंद नौटियाल शामिल रहे।

हरिद्वार में 26 फरवरी से औद्योगिक एवं फार्मा प्रदर्शनी, उद्योगों को मिलेगा नई तकनीक का मंच

पथ प्रवाह, हरिद्वार

जनपद में औद्योगिक विकास को नई गति देने और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से 26 फरवरी से तीन दिवसीय औद्योगिक एवं फार्मा प्रदर्शनी तथा उत्तराखंड फार्मा समिट का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन लघु उद्योग भारती और एमटेक इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में सिडकुल स्थित प्रदर्शनी मैदान में 26 से 28 फरवरी तक आयोजित होगा।

प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री रोहित भाटिया ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और छोटे एवं मझोले उद्योगों को नई तकनीक, आधुनिक मशीनों और नवीनतम औद्योगिक नवाचारों से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि अक्सर छोटे उद्योग आधुनिक तकनीक और मशीनों की जानकारी के अभाव में प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि इस

प्रदर्शनी और फार्मा समिट में देशभर की विभिन्न औद्योगिक इकाइयां और फार्मा कंपनियां भाग लेंगी और अपने नवीनतम उत्पादों, मशीनों तथा तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन करेंगी। इसके साथ ही मशीन निर्माताओं, लैब उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और पैकेजिंग विशेषज्ञों को एक ही मंच पर लाया जा रहा है, जिससे उद्योगों को अपनी जरूरत के अनुसार तकनीकी समाधान प्राप्त करने में सुविधा होगी।

रोहित भाटिया ने कहा कि इस आयोजन से स्थानीय उद्योगों को न केवल नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने नेटवर्क का विस्तार करने और व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। इससे उत्तराखंड के औद्योगिक क्षेत्र को मजबूती मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

प्रेसवार्ता के दौरान लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित त्यागी, हरिद्वार जिला अध्यक्ष मनोज पुंडीर, जिला महामंत्री निखिल गोयल, उपाध्यक्ष विनय, सुरजीत भुल्लर, गजेंद्र सिंह सहित संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। आयोजकों ने अधिक से अधिक उद्योगों, उद्यमियों और तकनीकी विशेषज्ञों से इस प्रदर्शनी में भाग लेकर इसका लाभ उठाने की अपील की है।

संपादकीय

मजबूत केंद्र-राज्य समन्वयः उत्तराखंड के विकास के लिए सुनहरा अवसर

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए विकास की राह हमेशा चुनौतियों से भरी रही है। सीमित संसाधन, कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ और अवसंरचनात्मक बाधाएँ राज्य की प्रगति को प्रभावित करती रही हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय विकास की गति को तेज करने का सबसे प्रभावी माध्यम बनता है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच स्थापित बेहतर संवाद और विश्वास ने उत्तराखंड को कई महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं।

हाल ही में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा ?500 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत किया जाना इसी समन्वय का एक प्रमुख उदाहरण है। कुंभ जैसे आयोजन केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का बड़ा अवसर भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार की सहायता से सड़क, पुल, पेयजल, स्वच्छता और यातायात जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास संभव होगा, जिसका लाभ आयोजन के बाद भी लंबे समय तक मिलता रहेगा। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल का सकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। सड़क और रेल संपर्क में सुधार, हवाई अड्डों के विस्तार और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलने से राज्य में निवेश और रोजगार की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। वित्तीय सहायता का वास्तविक महत्व तभी साबित होता है, जब योजनाएँ धरातल पर उतरकर आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। उत्तराखंड जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील राज्य में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के संतुलन को बनाए रखना भी आवश्यक है। केंद्र-राज्य समन्वय उत्तराखंड के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। यदि इस समन्वय को प्रभावी प्रशासन और दूरदर्शी योजना के साथ जोड़ा जाए, तो यह राज्य के समग्र विकास को नई दिशा दे सकता है और उत्तराखंड को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से और अधिक सशक्त बना सकता है।

कार्टेल के खिलाफ जंग और मेक्सिको की अग्निपरीक्षा

सनत जैन

मेक्सिको में कुख्यात ड्रग सरगना नेमेंसियो ओसेगेरा सर्वांतेस उर्फ 'एल मेंचो' के मारे जाने की खबर के बाद हुई भारी हिंसा से मेक्सिको को अनिश्चितता के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। आम जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आई है। नशे के कारोबार में (सीजेएनजी) प्रमुख के रूप में ड्रग लॉर्ड को न केवल मेंक्सिको, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का केंद्रीय चेहरा माना जाता था। मेक्सिको की सरकार इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है। किंतु ड्रग सरगना के मारे जाने के तुरंत बाद भड़की आगजनी, हाईवे जाम और सुरक्षा कर्मियों पर हमले से यह सवाल उठता है, क्या किसी सरगना के मारे जाने पर जनता का विद्रोह इस रूप में देखने को मिल सकता है? एल मेंचो पर अमेंरिका की सरकार ने बड़ा इनाम घोषित किया था। डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल से ही मेक्सिको पर ड्रग तस्करी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का दबाव अमेंरिका की सरकार बनाती रही है। फेंटानिल संकट ने अमेंरिका की आंतरिक राजनीति को झकझोर दिया है, इसका प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ना तय है। मेक्सिको की हिंसा केवल आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि इसका असर अमेंरिका सहित अन्य देशों पर भी पड़ना तय है। यह घटना भू-राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ी दिखती है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह मेक्सिको की संप्रभु रणनीति का हिस्सा है, या अमेंरिकी दबाव का परिणाम है। इतिहास बताता है कि कार्टेल के शीर्ष नेता को मार देने से इस समस्या का हल नहीं होता है। इससे ड्रग के कारोबार, राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों में स्थिरता संभव नहीं है। 2016 में जोक्विन एल चापो गुजमान की गिरफ्तारी के बाद भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आम जनता और सत्ता के बीच संघर्ष बढ़ा था। संगठित अपराध का नेटवर्क समानांतर व्यवस्था की तरह संचालित होता है। एक चेहरा हटता है, तो उसके कई दावेदार उभरते हैं। गैंग में वर्चस्व की लड़ाई आम नागरिकों की सुरक्षा और जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है। एल मेंचो की मौत के बाद इस तरह की घटनाएं इसी आशंका को पुष्ट कर रही हैं। ड्रग कारोबार और राजनीतिक संरक्षण का मूल मेक्सिको, अमेंरिका एवं कई अन्य देशों तक फैला हुआ है। दशकों से मेक्सिको में फैली गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक संघर्ष, भ्रष्टाचार और कमजोर तथा भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था से जुड़ता है। मेक्सिको के सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक पकड़ हमेंशा से कमजोर रही है। नशे के कारोबारी और इससे जुड़े हुए लोगों की समानांतर सत्ता चलती है। नशे के कारोबार में लगे अपराधी तत्व जिस तरह से काम करते हैं, उससे स्थानीय कारोबारियों को वसूली के डर से नियंत्रण और सीमापार तस्करी इनके साधन हैं। ऐसे में सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं हो सकती है। मेक्सिको सरकार के लिए यह दोहरी चुनौती है। एक ओर सरकार के ऊपर तत्काल कानून-व्यवस्था बहाल कर नागरिकों में भरोसा कायम करना है, दूसरी ओर दीर्घकालिक सुधारों पर गंभीरता से काम करना होगा।

मेक्सिको में न्यायिक पारदर्शिता, गवाहों की सुरक्षा, नशे की कारोबार में नेटवर्क पर वित्तीय प्रहार और पुलिस सुधार अनिवार्य है। सरकार, पुलिस और प्रशासन के बीच का भ्रष्टाचार रोकना, संस्थागत ढांचे को मजबूत नहीं किया तो यह 'जीत' अस्थायी साबित होगी। इसके साथ ही, इसका असर अमेंरिका में भी पड़ना तय है। अमेंरिका की सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब तक अमेंरिका में नशीली दवाओं की मांग बनी रहेगी, आपूर्ति के नए रास्ते और नए गिरोह समय-समय पर उभरते रहेंगे। नशे का कारोबार केवल मेक्सिको की समस्या नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इससे निपटने के लिए साझा जिम्मेंदारी जरूरी है। दबाव की नीति के बजाय सहयोग, खुफिया साझेदारी और सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा। एल मेंचो का अंत प्रतीकात्मक जीत हो सकती है, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। यदि मेक्सिको में सुशासन और पारदर्शिता चाहिए तो भुखमरी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सामाजिक निवेश की ठोस रणनीति बनानी होगी। तभी नशे के कारोबार के गैंगस्टरों की छाया से मेक्सिको बाहर निकल पाएगा। इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं करता है। नशे के कारोबार का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, इसमें भारी पैसा है। इस नेटवर्क को इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से अभी कार्रवाई की गई है। कार्यवाही के पश्चात जिस तरह के हालात मेक्सिको के बन गए हैं, उस चुनौती से निपटना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका इस मामले में मेक्सिको की क्या मदद करता है, यह भी देखना होगा।

राजस्थान में बसों के पहिए थमे, जिम्मेदारी भी ठहरी प्रशासन की सुस्ती से यात्री सड़कों पर

कांतिलाल मांडोत

राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने आमजन के सामने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जब परिवहन व्यवस्था का बड़ा हिस्सा निजी हाथों में हो और वह अचानक ठप हो जाए, तो प्रशासन की वैकल्पिक तैयारी कहाँ है। जयपुर, कोटा, अजमेर, सीकर और उदयपुर सहित कई शहरों में सोमवार रात 12 बजे से निजी बसों का संचालन रुक गया। ऑपरेटर्स का दावा है कि प्रदेश की लगभग 35 हजार कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, स्टेज कैरिज और लोक परिवहन बसें बंद हैं, जिनसे प्रतिदिन 15 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं। यदि यह आंकड़ा सही है तो यह केवल हड़ताल नहीं, बल्कि प्रदेश की जीवनरेखा पर लगा ब्रेक है।

राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह से लंबी कतारें दिखाई दीं। यात्री घंटों इंतजार करते रहे, कई को बसें नहीं मिलीं। रोडवेज बसों में ठसाठस भीड़ रही। पुलिसकर्मी यात्रियों को लाइन में चढ़ाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल लाइन लगवाना ही प्रशासनिक तैयारी कहलाता है। कोटा के बालाजी मार्केट बस स्टैंड से एक भी निजी बस नहीं निकली। सीकर में भी निजी बसें बंद रहीं। अजमेर में तो निजी बस ऑपरेटर्स ने 28 फरवरी को होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के लिए भी बसें उपलब्ध न कराने की घोषणा कर दी। हालांकि जोधपुर में हड़ताल का असर सीमित रहा और कई निजी बसें सामान्य रूप से चलती रहीं, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि स्थिति पूरी तरह एकसमान नहीं है।

हड़ताल का कारण परिवहन विभाग की कार्रवाई को बताया जा रहा है। बस संचालकों का आरोप है कि आरसी सस्पेंड की जा रही हैं, भारी-भरकम चालान काटे जा रहे हैं, पुरानी गाड़ियों पर धारा 153 लगाई जा रही है, रास्ते में सवारियों से भरी बसों को खाली कराया जा रहा है और लगेज कैरियर लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही। यदि विभाग नियमों का पालन करवा रहा है तो पारदर्शिता के साथ संवाद क्यों नहीं हो पाया। यदि कहीं अति हो रही है तो उसका परीक्षण क्यों नहीं हुआ। सचिवालय में वार्ता के बावजूद सहमति न बन पाना प्रशासनिक संवादहीनता का संकेत है।

कटाक्ष यह है कि हमारे प्रशासनिक तंत्र को अक्सर संकट के बाद सक्रिय होते देखा जाता है। जब हजारों यात्री बस स्टैंड पर भटकने लगते हैं, तब अतिरिक्त बसों की घोषणा की जाती है। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो राउंड बढ़ाए जाएंगे। प्रश्न यह है कि जरूरत का आकलन पहले क्यों नहीं किया गया। यदि प्रदेश में 15 लाख से अधिक लोग प्रतिदिन निजी बसों से यात्रा करते हैं तो हड़ताल की आशंका भर से एक आपात योजना तैयार हो जानी चाहिए थी। केवल बयान जारी कर देना कि व्यवस्था कर ली जाएगी, पर्याप्त नहीं है।

उदयपुर में ट्रैवल्स एसोसिएशन के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जिन बसों का रजिस्ट्रेशन विभाग ने किया, उन्हीं के परमिट निरस्त किए जा रहे हैं और फिटनेस रद्द की जा रही है। यदि यह सही है तो नीति और क्रियान्वयन में तालमेल की कमी स्पष्ट है। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह पर अड़े हैं, लेकिन पीस रहा है आम यात्री। होली और खाटूश्याम मेले के कारण पहले से ही भीड़ अधिक है। ऐसे समय में परिवहन ठप होना केवल असुविधा नहीं, बल्कि प्रशासनिक असंवेदनशीलता का उदाहरण बन जाता है।

प्रशासन की जवाबदेही केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं हो सकती। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कानून लागू करते समय जनजीवन बाधित न हो। परिवहन विभाग को चाहिए कि वह स्पष्ट और लिखित गाइडलाइन जारी करे जिसमें यह बताया जाए कि किन परिस्थितियों में आरसी सस्पेंड होगी, किन मामलों में धारा 153 लगेगी, चालान की अधिकतम सीमा क्या होगी और अपील की प्रक्रिया क्या है। यदि नियम स्पष्ट और समान रूप से लागू होंगे तो विवाद की गुंजाइश कम होगी। साथ ही एक संयुक्त समन्वय समिति बनाई जा सकती है जिसमें परिवहन विभाग, रोडवेज और निजी बस संघों के प्रतिनिधि शामिल हों, ताकि किसी भी कार्रवाई से पहले संवाद का रास्ता खुला रहे।

सरकार को यह भी समझना होगा कि निजी बसें केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवा का हिस्सा हैं। यदि 35 हजार बसें बंद होती हैं तो उसका सीधा असर श्रमिकों, विद्यार्थियों, मरीजों और छोटे व्यापारियों पर पड़ता है। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी परमिट जारी कर अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जा सकती हैं। जरूरत पड़े तो पड़ोसी राज्यों से समन्वय कर बसों की अस्थायी तैनाती की जा सकती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए ताकि यात्रियों को पहले से पता हो कि कौन-सी बसें चल रही हैं और कौन-सी नहीं। बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं और किराए में अनावश्यक बढ़ोतरी पर निगरानी रखी जाए।

प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हड़ताल के दौरान किसी प्रकार का चक्का जाम या अवरोध आमजन के लिए नई समस्या न बने। कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण वार्ता को प्राथमिकता दी जाए। यदि कुछ अधिकारी अपनी कार्रवाई से अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं तो उनकी भी जवाबदेही तय हो। पारदर्शी जांच और समयबद्ध समाधान ही विश्वास बहाल कर सकते हैं।

निजी बस संचालकों की मांगें पूरी तरह सही हैं या नहीं, यह अलग विषय है, लेकिन यह तय है कि व्यवस्था का भार केवल यात्रियों पर नहीं डाला जा सकता। सरकार और प्रशासन को मिलकर ऐसी ठोस और दीर्घकालिक नीति बनानी होगी जिससे नियमों का पालन भी हो और सेवा भी बाधित न हो। परिवहन जैसी मूलभूत सुविधा को टकराव का माध्यम नहीं बनने दिया जा सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन सक्रिय, संवेदनशील और जवाबदेह बने, ताकि बसों के पहिए फिर चलें और जनता को राहत मिले।

होलाष्टक से धूलिवंदन तक-चंद्रग्रहण, आस्था, ज्योतिष और व्यवहारिकता के बीच संतुलन

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

होली केवल भारत तक सीमित नहीं,बल्कि विश्वभर में बसे भारतीय समुदायों और विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। होलाष्टक की मान्यताएं हमें संयम,अनुशासन और आत्मचिंतन का संदेश देती हैं, जबकि होली का रंगोत्सव हमें प्रेम, क्षमा और नई शुरुआत का अवसर देता है वैश्विक स्तरपर होली का त्योहार केवल रंगों काउत्सव नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की जीवंतता,आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। भारत सदियों से विविध आस्थाओं,प्रथाओं और मान्यताओं का केंद्र रहा है,जहां हर पर्व को शुद्ध श्रद्धा और सांस्कृतिक अनुशासन के साथ मनाया जाता है। यही कारण है कि होली केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि विश्वभर में बसे भारतीय समुदायों और विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है।2026 में होली का पर्व विशेष चर्चा में है, क्योंकि 24 फरवरी से होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है, 2 मार्च को होलिका दहन होगा और 3 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही 3 मार्च को चंद्रग्रहण होने की चर्चा ने लोगों के मन में यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि धूलिवंदन 3 मार्च को होगा या 4 मार्च को? इस लेख में हम धार्मिक मान्यताओं,ज्योतिषीय दृष्टिकोण और व्यवहारिक तथ्यों के आधार पर इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करेंगे।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि हम सब जानते हैं कि,पौराणिक आधार पर होली की जड़ें भगत प्रहलाद, होलिका और नरसिम्हा की कथा से जुड़ी हैं। असत्य पर सत्य की विजय और अहंकार के अंत का संदेश देने वाली यह कथा भारतीय मानस में गहराई से रची-बसी है।होलिका दहन उस प्रतीकात्मक क्षण का स्मरण है जब भक्ति और धर्म की रक्षा हुई। इसलिए होली केवल रंगों का खेल नहीं,बल्किआध्यात्मिक पुनर्जागरण का अवसर भी है इस आर्टिकल में चर्चा की गई हर बात मान्यताओं पर आधारित सटीकता से इसका कोई संबंध नहीं वह यहां लिखी हुई बातें मानी जाए यह बिलकुल जरूरी नहीं है। साथियों बात अगर हम होलाष्टक 2026: अवधि और धार्मिक मान्यता इसको समझने की करें तो,2026 में होलिका दहन 2 मार्च को पड़ रहा है, अतः उससे आठ दिन पूर्व 24 फरवरी से होलाष्टक प्रारंभ होगा और 3 मार्च तक चलेगा। होलाष्टक का अर्थ है होली से पहले के आठ दिन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों में आठ प्रमुख ग्रह उग्र अवस्था में माने जाते हैं,अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध,चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु। मान्यता है कि इस अवधि में शुभ और मांगलिक कार्य करने से जीवन में बाधाएं,कलह या कष्ट आ सकते हैं।इसलिए विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, वाहन क्रय, भूमि पूजन और नए व्यवसाय की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है।हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये मान्यताएं ज्योतिषीय परंपराओं पर आधारित हैं,न कि किसी विधिक अनिवार्यता पर।भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन मान्यताओं का पालन अलग- अलग स्तर पर किया जाता है। कुछ समुदाय इसे कठोरता से मानते हैं,जबकि कुछ इसे प्रतीकात्मक मानकर अपनी सामान्य जीवनचर्या पूर्वोतःजारी रखते हैं। साथियों बात अगर हम चंद्रग्रहण और धूलिवंदन का भ्रम इसको समझने की करें तो,2026 में 3 मार्च को चंद्रग्रहण होने की चर्चा के कारण यह भ्रम फैल रहा है किधूलिवंदन 4 मार्च को मनाया जाना चाहिए। यहां मूल सिद्धांत यह है कि होली का रंगोत्सव पूर्णिमा तिथि के अगले दिन, अर्थात होलिका दहन के बाद मनाया जाता है। यदि 2 मार्च की रात्रि में होलिका दहन हो रहा है और पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को विद्यमान है, तो परंपरागत रूप से रंगों की होली 3 मार्च को ही मनाई जाने की संभावना है।चंद्रग्रहण का प्रभाव मुख्यतःतब माना जाता है जब वह भारत में दृश्य हो और उसके समय का संयोग महत्वपूर्ण पूजा-विधि से हो। यदि ग्रहण का समय रंग खेलने के पारंपरिक समय से भिन्न है या वह भारत में दृश्य नहीं है, तो सामान्यतः होली की तिथि नहीं बदलती। इसलिए केवल ग्रहण की उपस्थिति से धूलिवंदन की तिथि स्वतः 4 मार्च नहीं हो जाती ऐसा कुछ लोगों का मानना है।अंतिम निर्णय पंचांग,स्थानीय परंपरा और मंदिरसमितियों की घोषणा पर निर्भर करता है।इसलिए व्यापक रूप से 3 मार्च 2026 को ही रंगोत्सव मनाया जाना संभावित है,जबतक कि अधिकृत पंचांग बिल्कुल ही अन्यथा न कहे। साथियों बात अगर हम हिंदू धर्म के 16 संस्कारों क़ा संक्षिप्त परिचय जानने की करें तो हिंदू जीवन-पद्धति में 16 संस्कारों का उल्लेख है, जो जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन को पवित्र और अनुशासित बनाते हैं।

एक नजर

रिकवर किए गए 13 मोबाइल फोन उनके स्वामियों को लौटाये

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मुख्यालय स्तर पर जारी निर्देशों के क्रम में कोतवाली रानीपुर पुलिस ने थाना प्रांगण में 'थाना दिवस' का आयोजन किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आशुतोष राणा ने स्टॉफ की उपस्थिति में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित कार्रवाई की। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। थाना दिवस के आयोजन के उपरांत रानीपुर पुलिस ने विभिन्न लोगों गुम हुये करीब 2 लाख 98 हजार रूपये के 13 मोबाइल फोन को ष्टश्वढ्ढक्रपोर्टल के माध्यम से बरामद कर उक्त मोबाइल फोनों को उनके स्वामियो के सुपुर्द किया गया। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरो पर मुस्कान लौटी।

साइबर ठगी के 50 हजार वापस दिलाकर हरिद्वार पुलिस ने लौटायी खुशी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। साइबर ठगी में गवांए पैसों में से 50 हजार रुपये वापस दिलाकर कोतवाली मंगलौर पुलिस ने पीड़ित को उम्मीद जगायी है। एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में मुरझाये चेहरों पर मुस्कान लाकर हरिद्वार पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है। बताया गया कि जनवरी माह में फैक्ट्री में कार्यरत के साथ पीएफ चालान प्रेषित करने के बाद पीड़ित के साथ 50,000 का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। पीड़ित ने तुरंत कोतवाली मंगलौर को सूचित किया जिसके बाद कांस्टेबल ज़फ़र द्वारा तुरंत पत्राचार करते हुए अकाउंट फ्रीज कराया गया था। समय रहते त्वरित कार्रवाई से 50 हज़ार रुपये वापस लौटाए गए। पुलिस के मुताबिक 25.01.2026 को सूचना प्राप्त हुई थी कि पंकज कुमार पुत्र मेघराज निवासी सहारनपुर, जो कोतवाली मंगलौर क्षेत्र की एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं, के साथ पीएफ चालान प्रेषित करने के बाद 50,000 रुपये का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। सूचना मिलते ही थाने में नियुक्त कांस्टेबल जफर हुसैन द्वारा संबंधित बैंक/एजेंसी से तत्काल पत्राचार कर संदिग्ध खाते को फ्रीज़ कराया गया। कुशल तकनीकी सहायता एवं त्वरित समन्वय के फलस्वरूप दिनांक 24.02.2026 को पूरी 50,000 रुपये की धनराशि पीड़ित को वापस दिलाई गई। पैसे वापस मिलने पर पीड़ित ने उत्तराखंड पुलिस का आभार व्यक्त किया। सभी को हरिद्वार पुलिस का संदेश है कि किसी भी अनचाहे लिंक पर क्लिक न करें। ऑनलाइन प्रलोभन, लॉटरी या अनजाने कॉल के झांसे में न आएं। यदि साइबर ठगी का शिकार हो जाएं तो तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

एटीएम तोड़कर नगदी चुराने से पहले शातिर चोर को पुलिस ने दबोचा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रावली महदूद सिडकुल निवासी कुलदीप जोशी ने कोतवाली रानीपुर पर सूचना दी कि दिनांक 21.02.2026 की रात्रि को शिवलोक कालोनी में स्थित WLA SPOT के ए0टी0एम0 में एक अज्ञात चोर द्वारा घुसकर ए0टी0एम0 का लॉक तोडकर चोरी करने का प्रयास किया गया। सूचना पर मु0अ0सं0 56/2026 धारा 305(ए),62,324(4) बी0एन0एस0 दर्ज कर विवेचना शुरु की गई। प्रकरण में प्रकाश में आए संदिग्ध की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने सुरागरसी-पतारसी के आधार पर कल दिनांक 23.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर वॉटर वर्क्स शिवलोक में स्थित ग्राउण्ड के पास से पहले भी चोरी के मामले में कुख्यार रह चुके लविश को दबोचकर उसके कब्जे से .ञ्ज.रू का टूटा हुआ लॉक व चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए। आरोपी ने पूछताछ में बताय कि वह पहले भी चोरी ओर अवैध अस्लाह के मुकदमों में जेल गया था एवं कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया। मुकदमें एवं अन्य खर्चो को पूरा करने के लिए शातिर ने ए0टी0एम0 तोड़कर नगदी जुटाने की योजना बनाई लेकिन असफल रहा। आरोपी लविश उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमें में धारा 331(4)BNS की बढोत्तरी कर उसे आज मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

औचक निरीक्षण में मेडिकल स्टोर्स और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच

पथ प्रवाह, पौड़ी। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों तथा जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल के आदेशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल की सचिव नाजिश कलीम के नेतृत्व में दिनांक 24 फरवरी 2026 को 'सुरक्षित दवा, सुरक्षित जीवन' एवं 'जेनेरिक ड्रग्स - इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एंड एसेंशियल' अभियान के अंतर्गत श्रीनगर बाजार स्थित मेडिकल स्टोर्स एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य एक्सपायरी एवं अमानक दवाओं तथा असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करना रहा।

निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध दवाओं की एक्सपायरी तिथि, भंडारण व्यवस्था, आवश्यक लाइसेंस, अभिलेखों का संधारण तथा जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता का गहन परीक्षण किया गया। दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि किसी भी स्थिति में एक्सपायरी अथवा निम्न गुणवत्ता की दवाओं का विक्रय न करें तथा जनसामान्य को किफायती एवं प्रभावी उपचार के लिए जेनेरिक दवाओं के उपयोग के प्रति जागरूक करें।

खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण में स्वच्छता एवं भंडारण से संबंधित कुछ कमियां सामने आने पर समिति ने कार्रवाई करते हुए मावा, गुजिया, मिल्क केक एवं रबड़ी सहित 05 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। साथ ही 03 प्रतिष्ठान संचालकों को मौके पर ही कमियों से अवगत कराते हुए तत्काल सुधार करने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण दल ने स्पष्ट किया कि एक्सपायरी दवाओं अथवा अमानक खाद्य सामग्री की बिक्री कानूनन दंडनीय अपराध है। भविष्य में ऐसी किसी भी लापरवाही के पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के माध्यम से संबंधित व्यवसायियों को जनस्वास्थ्य की संवेदनशीलता के प्रति जागरुक करते हुए नियमों के अनुरूप कार्य करने की हिदायत दी गई।

संयुक्त निरीक्षण में आयुक्त खाद्य सुरक्षा पी.सी. जोशी, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक विमल गुसाईं, औषधि निरीक्षक सीमा बिष्ट चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप मिश्रा एवं रचना लाल, पूर्ति निरीक्षक विजय, सब-इंस्पेक्टर जगमोहन रमोला, मुकेश भट्ट तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बाल श्रम रोकने के लिए दिए कड़े निर्देश

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने मंगलवार को जिला बाल कल्याण समिति की समीक्षा बैठक लेते हुए बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके।उन्होंने जिले में नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए ताकि समाज के हर वर्ग को बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। जिलाधिकारी ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण थीम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एनएसएस और अन्य माध्यमों से बाल विवाह और घरेलू हिंसा पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रा मार्गों और पड़ावों पर बाल श्रम को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं तथा बच्चों से श्रम कराया जाता मिलने पर संबंधित के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने जेजे एक्ट से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यवाहियों में तेजी लाएं एवं मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए जरूरी कार्यवाही करें। बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी शोयब हुसैन, अध्यक्ष सीडब्लूसी पुष्पा चौहान सहित अन्य उपस्थित रहे।

जनपद स्थापना दिवस की जिलाधिकारी ने दी हार्दिक शुभकामनाएं

0पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य उत्तकाशी जनपद के स्थापना दिवस पर बधाई संदेश में कहा कि 24 फरवरी 1960 को स्थापित उत्तरकाशी जनपद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से समृद्ध रहा है। यहां की गौरवशाली परंपराएं, विविधतापूर्ण संस्कृति और विकास की निरंतर प्रगति हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि जनपद की उन्नति में किसानों, श्रमिकों, शिक्षकों, उद्यमियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रशासन जनपद के समग्र विकास, सुशासन एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनपद की निरंतर प्रगति की कामना के साथ सभी क्षेत्रवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

डॉ. रमेश कुंवर अध्यक्ष और डॉ. यशपाल तोमर महासचिव निर्वाचित

पथ प्रवाह, देहरादून।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड के द्विवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गए। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. नरेश नपलच्याल एवं चुनाव अधिकारी डॉ. अमलेश सिंह की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई।

नई कार्यकारिणी में डॉ. यशपाल तोमर को महासचिव चुना गया। डॉ. सौरभ सिंह उपाध्यक्ष (मुख्यालय), डॉ. लोकेश सालूजा उपाध्यक्ष (क्षेत्र), डॉ. गरिमा भट्ट उपाध्यक्ष (महिला) तथा डॉ. उपेंद्र सिंह पंवार उपाध्यक्ष (दंत) निर्वाचित हुए। कोषाध्यक्ष पद पर डॉ. राजीव कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई।

अतिरिक्त महासचिव (कुमाऊं) के रूप में डॉ. दीपक शर्मा और अतिरिक्त महासचिव (गढ़वाल) के रूप में डॉ. मनीष कुमार चुने गए। डॉ. राशि रंजन कुकरेती को संपादक, डॉ. रचित गर्ग को मीडिया प्रभारी तथा डॉ. सुमित नारायण अवस्थी को प्रभारी तकनीकी सेल बनाया गया। नई केंद्रीय कार्यकारिणी को महानिदेशक सुनीता टम्टा, निदेशक डॉ. शिखा जंगपांगी और निदेशक आरसीपीएन ने बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि टीम चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने और चिकित्सकों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएगी।

कार्यकारिणी गठन के अवसर पर डॉ. अजीत मोहन जोशी, डॉ. जेएस चुफाल, डॉ. शैलेंद्र कंडारी, डॉ. बीएस नेगी, डॉ. तुहिन कुमार, डॉ. पंकज शर्मा, डॉ. वीपी सिंह, डॉ. नलिन असवाल, डॉ. परमर्थ जोशी, डॉ. अनमोल सिंह, डॉ. मनीष शर्मा, डॉ. पवन कार्की और डॉ. नवनीत चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड में बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन की तैयारी

पथ प्रवाह, देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य की बढ़ती भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भवन निर्माण नियमों को अधिक सुरक्षित और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारतीय मानक ढ्ढस्ह्र 1893-2025 के अनुसार पूरे राज्य के भूकंप जोन छह में शामिल होने के बाद अब बिल्डिंग बायलॉज में व्यापक संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा वर्तमान बिल्डिंग बायलॉज की समीक्षा एवं संशोधन हेतु सीएसआईआर-सीबीआरआई रुड़की के निदेशक प्रो आर प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यूएलएमएमसी के निदेशक डॉ. शांतनु सरकार को समिति का संयोजक बनाया गया है। बता दें कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में बिल्डिंग बायलॉज भारतीय मानक ब्यूरो के पुराने संस्करण ISO 1893-2002 पर आधारित हैं। समिति में सीबीआरआई रुड़की, भारतीय मानक ब्यूरो, आईआईटी, ब्रिडकुल, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, विकास प्राधिकरणों तथा भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञों सहित विभिन्न तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति वास्तुविदों के साथ ही विभिन्न अभियंताओं से भी विचार-विमर्श करेगी।

एक नजर

पार्थ सारथी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जनपद पुलिस द्वारा संचालित जागरूकता अभियान 'पुलिस आपके द्वार' के अंतर्गत कोतवाली नगर हरिद्वार पुलिस टीम ने पार्थ सारथी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खड़खड़ी में महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता अभियान के दौरान महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानून, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन 1090 / 1091, साइबर अपराध से बचाव के उपाय के साथ साथ छेड़छाड़ एवं घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे बिना संकोच पुलिस से संपर्क करें, पुलिस सदैव आपकी सहायता एवं सुरक्षा हेतु तत्पर है। साथ ही आत्मरक्षा के सामान्य उपाय एवं सतर्कता संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए गए। स्थानीय नागरिकों एवं विद्यालय परिवार द्वारा इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज में सुरक्षा एवं विश्वास बढ़ाने वाला प्रभावी कदम बताया गया तथा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की गई।

गौरा शक्ति मिशन बैठक में छात्राओं को किया गया जागरूक

पथ प्रवाह, हरिद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर जनपद पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत खानपुर पुलिस ने छात्र छात्राओं के अलावा ग्रामीण महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया। थाना खानपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले कन्या इन्टर कॉलेज में गौरा शक्ति मिशन के सन्दर्भ में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं व शिक्षक वर्ग उपस्थित रहे। सभी को पुलिस द्वारा उत्तराखण्ड़ पुलिस एप की प्रक्रिया, यातायात नियमों, साइबर अपराध किस-किस प्रकार से हो सकते है एवं उनसे बचाव के तरीकों, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, मानव तस्करी, आपातकालीन नम्बर डायल-112, साइबर हेल्पलाइन नम्बर-1930, सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति एवं दुष्प्रभाव, सोशल नेटवर्किंग साइट की जानकारी एवं सोशल मीडिया पर बरती जाने वाली सावधानियों, एटीएम/बैंक फ्रॉड व किसी प्रकार के बाहरी / संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी पुलिस को देने व अपराध की रोकथाम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए जागरूक किया। खानपुर पुलिस का गौरा शक्ति मिशन अन्य अभियानों को व्यापक एवं सफल बनाने हेतु प्रयास जारी है ।

ट्रक चोरी का हरिद्वार पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। थाना भगवानपुर के हबीबपुर निवादा निवासी सतीश कुमार ने कोतवाली गंगनहर में आकर शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए बताया था कि उसका 6 टायरा ट्रक किसी अज्ञात चोर ने रात के समय चोरी कर लिया है। प्राप्त शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने उक्त प्रकरण में मु0अ0स0- 0079/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया तथा अलग-अलग टीमें गठित कर चुराए गए ट्रक व अज्ञात आरोपित की तलाश शुरु की। निरंतर प्रयास के पश्चात पुलिस टीम ने दिनांक 24.02.2026 को सालियर अण्डर के पास से चोरी किए गए ट्रक को बरामद करते हुए 01 आरोपित को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ में सामने आए कि पकड़ा गया संदिग्ध पेशे से मैकेनिक है और ट्रक चोरी करने के बाद उसने ट्रक में लगी जीपीएस डिवाइस हटाने के भी प्रयास किए लेकिन ज्यादा नशे में होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की वृद्धि कर आरोपित को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

भूमि की रजिस्ट्री का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, डीएम के निर्देश पर क्रेता-विक्रेता पर मुकदमा दर्ज

पथ प्रवाह, देहरादून

जनपद में न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित भूमि के अवैध क्रय-विक्रय से जुड़े गंभीर फर्जीवाड़े के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाते हुए क्रेता और विक्रेता के खिलाफ थाना शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य की कृषि और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से खरीद-फरोख्त करने वाले भू-माफियाओं और बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिलाधिकारी सविन बंसल के संज्ञान में मौजा आमवाला तरला स्थित खसरा संख्या 94ख, 134, 135 एवं 136 की भूमि का मामला आया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व से ही क्रय-विक्रय पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद संबंधित पक्षों द्वारा कूटरचित (फर्जी) अभिलेख तैयार कर उक्त भूमि की रजिस्ट्री करा ली गई। शिकायतकर्ता द्वारा विलेख संख्या 8614/2025 एवं 8615/2025 पर आपत्ति दर्ज कराते हुए बताया गया कि यह भूमि पीएसीएल (पर्ल्स एग्रो टेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से संबंधित प्रतिबंधित श्रेणी में आती है, जिस पर न्यायालय का स्पष्ट प्रतिबंध लागू है। प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि विक्रेता द्वारा भूमि की वास्तविक स्थिति और प्रतिबंध की जानकारी छिपाकर रजिस्ट्री कराई गई, जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के साथ-साथ एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। साथ ही, संबंधित भूमि का संबंध गोल्डन फॉरेस्ट से जुड़ी परिसंपत्तियों से भी बताया जा रहा है, जिन पर पूर्व से विभिन्न स्तरों पर प्रतिबंध लागू हैं। बताया जा रहा है कि बाहरी राज्यों, विशेषकर चंडीगढ़ और पंजाब से जुड़े बिल्डर्स और भू-माफिया प्रतिबंधित भूमि को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बेचने का प्रयास कर रहे हैं।

जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार देहरादून और उप जिलाधिकारी सदर को संबंधित विलेखों की पुनः जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, यदि इन दस्तावेजों के आधार पर दाखिल-खारिज की कार्रवाई की गई है, तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश भी तहसील प्रशासन को दिए गए हैं।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 83 के तहत कूटरचना कर भूमि पंजीकरण कराने के मामले में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध थाना शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही सब-रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है और प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन जल्द ही ऋषिकेश सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की तर्ज पर देहरादून रजिस्ट्रार कार्यालय का व्यापक निरीक्षण भी कर सकता है।

उत्तरकाशी में ऐच्छिक ब्यूरो की काउंसलिंग से 5 पारिवारिक विवाद सुलझे

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

पुलिस कार्यालय उत्तरकाशी में मंगलवार को ऐच्छिक ब्यूरो कमेटी की ओर से पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी श्रीमती कमलेश उपाध्याय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें महिला काउंसलिंग सेल के पास लंबित पारिवारिक मतभेद एवं कलह के कुल पांच मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।

एसपी कमलेश उपाध्याय ने कहा कि अक्सर गलतफहमियां ही परिवारों के टूटने का प्रमुख कारण बनती हैं। छोटी-छोटी बातों पर उत्पन्न विवाद रिश्तों में दूरी और कड़वाहट ला देते हैं। यदि परिवार के सदस्य खुलकर संवाद करें, एक-दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझें तथा धैर्य और क्षमाशीलता का परिचय दें तो अधिकांश विवाद सहज रूप से सुलझाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रिश्ते बनाना कठिन है, जबकि तोड़ना आसान होता है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जनपद में पुलिस महिला काउंसलिंग सेल को प्राप्त पारिवारिक मामलों में ऐच्छिक ब्यूरो कमेटी समय-समय पर काउंसलिंग कर टूटते हुए परिवारों को पुनः जोड़ने का प्रयास करती है। इसी उद्देश्य से आयोजित इस सत्र में दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान कराया गया। काउंसलिंग सत्र में पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी जनक सिंह पंवार, डॉ. प्रिया त्यागी (मनोचिकित्सक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी), डॉ. अनामिका क्षेत्री (प्रवक्ता, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी), अधिवक्ता श्रीमती राजकुमारी रमोला, श्रीमती नीतू राज (प्रवक्ता, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी) एवं महिला काउंसलिंग सेल प्रभारी श्रीमती गीता उपस्थित रहीं।

उत्तरकाशी में 'आप्रेशन क्रैक डाउन' तेज, 10 दिन में 700 सत्यापन

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी

जनपद में अपराध नियंत्रण एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार संचालित 'आप्रेशन क्रैक डाउन सत्यापन अभियान' के तहत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा बाहरी प्रान्तों से आकर निवास कर रहे व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी श्रीमती कमलेश उपाध्याय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर सत्यापन कराए जा रहे हैं, साथ ही आम नागरिकों को भी पुलिस सत्यापन के महत्व के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

अभियान के तहत मंगलवार को उत्तरकाशी पुलिस टीमों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान 66 व्यक्तियों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा सत्यापन प्रपत्र भरकर जांच के लिए संबंधित विभागों को भेजे गए। पुलिस द्वारा होटल, धर्मशाला, होम स्टे, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, पीजी, किराये के मकान, कोचिंग सेंटर, निर्माणाधीन परियोजनाओं, निजी संस्थानों तथा श्रमिकों, व्यवसायियों, रेहड़ी-ठेली संचालकों, कबाड़ियों एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में निवासरत बाहरी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका सत्यापन किया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, पिछले 10 दिनों के भीतर अभियान के तहत 700 से अधिक बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया जा चुका है। यह अभियान जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तरकाशी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें तथा अपने यहां किराए पर रहने वाले बाहरी व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराएं। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशाला संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने यहां ठहरने वाले पर्यटकों और आगंतुकों का पूरा विवरण, पहचान पत्र सहित दर्ज करें तथा विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य रूप से 'फॉर्म-सी' भरना सुनिश्चित करें।

एक नजर

पोखरी में कैरम प्रतियोगिता में 32 टीमों ने दिखाया दमखम

पथ प्रवाह, पोखरी/चमोली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पोखरी इकाई द्वारा 'खेलो भारत अभियान' के अंतर्गत कैरम प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में क्षेत्र की कुल 32 टीमों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर खेल भावना का परिचय दिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। फाइनल मुकाबले में गुडम मसोली के देवराज नेगी और सर्वेंद्र कुमार की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं रडुवा के रविशंकर और सोहन सिंह की टीम ने उपविजेता का खिताब अपने नाम किया। विजेता और उपविजेता टीमों को स्मृति चिन्ह एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर मंडल अध्यक्ष अमर रावत उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल गतिविधियां युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित करती हैं। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच मिलता है। इस अवसर पर पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ललित मिश्रा, नगर अध्यक्ष एबीवीपी शंकर डबराल, उर्मिला नेगी, जिला संयोजक सौरभ बर्तवाल, देवेंद्र नौटियाल, अमन गुसाई, दिव्यांशु, गजेंद्र और आशु बर्तवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

बिजली विभाग के खिलाफ जगजीतपुर बिजली घर पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मंगलवार को उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जगजीतपुर उपखंड अधिकारी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का जमकर विरोध किया। सात दिनों के अंदर उनकी मांगों पर कार्रवाई न होने पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड किसान मोर्चा युवा के जिलाध्यक्ष अक्षय कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को कार्यकर्ता उपखंड अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे और यहां बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना देकर बैठ गए। किसानों ने कहा कि उत्तराखंड के किसानों के ट्यूबवैलों की बिजली भी उत्तर प्रदेश की तरह फ्री की जाए। घरेलू बिजली के बकाया बिलों पर पेनाल्टी माफ की जाए। बिजली विभाग के कर्मचारी और विजीलेंस की टीम जिस तरह से बिजली चोरी पकड़ने के नाम पर सीढ़ी लगार असंवैधानिक तरीके से ग्रामीणों के घरों में घुस रही है उसे रोका जाए। उपभोक्ताओं के घरों के मीटर बकाया होने पर उतारे जा रहे पुराने मीटर और बाद में उनके स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का भी ग्रामीणों ने विरोध किया। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचे उपखंड अधिकारी रुपेश कुमार ने उनकी समस्याओं के समाधान का उचित आवश्वासन दिया। बताया कि बकाया बिलों को जमा कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ग्रामीण अभियान में सहयोग करें। स्मार्ट मीटर के बारे में जो भ्रम है उसे दूर किया जा रहा है। बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों की मांगों से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

कैप्टन रमेश बर्त्वाल के नेतृत्व में कर्नल अजय कोठियाल को सौंपा ज्ञापन

पथ प्रवाह, पोखरी। चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक के भूतपूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन रमेश बर्त्वाल के नेतृत्व में देहरादून पहुंचा। यहां उन्होंने पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल से शिष्टाचार भेंट कर पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान कैप्टन रमेश बर्त्वाल ने पोखरी क्षेत्र में यूथ फाउंडेशन कैंप खोले जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को सेना भर्ती की तैयारी के लिए उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे वे देश सेवा के लिए प्रेरित हो सकें। कर्नल अजय कोठियाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह शीघ्र ही क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के उपरांत यूथ फाउंडेशन कैंप खोलने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे तथा पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने सरकार से पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान देने की मांग की।

रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी ने स्वयं मैदान में उतरकर संभाला मोर्चा, संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात

पथ प्रवाह, नैनीताल

रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पूर्व जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैनीताल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के नेतृत्व में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं तथा पुलिस अधिकारियों और जवानों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था प्रभावित न होने दी जाए।

एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी स्वयं मैदान में उतरकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और पुलिस बल को फ्रंट से नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। संभावित संवेदनशीलता को देखते हुए जिले में एडिशनल एसपी, क्षेत्राधिकारी, निरीक्षक, उपनिरीक्षक सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त आईआरबी की एक कंपनी, पीएसी की प्लाटून, दंगा नियंत्रण वाहन, बम निरोधक दस्ते, फायर टेंडर और सीपीयू की टीमें भी तैनात की गई हैं। पुलिस द्वारा जनपद में सघन

सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है तथा सीमाओं पर विशेष चेकिंग की जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी सुनिश्चित की गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने आमजन से अपील की है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अफवाह फैलाने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लीसा विदोहन, एग्रो फॉरेस्ट्री व वन संरक्षण के माध्यम से आजीविका सुदृढ़ करने पर जोर

पथ प्रवाह, पौड़ी।

वन विभाग के तत्वावधान में मध्य हिमालयी क्षेत्र में चीड़ आधारित रोजगार की संभावनाओं विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रेक्षागृह, पौड़ी में किया गया। कार्यशाला में लीसा विदोहन के माध्यम से रोजगार सृजन, 'चीड़ एक कल्पवृक्ष' विषय, मध्य हिमालयी क्षेत्र में चीड़ का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व तथा एग्रो फॉरेस्ट्री की संभावनाओं एवं चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला ने प्रतिभाग करते हुए दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मध्य हिमालयी क्षेत्र में चीड़ स्थानीय आजीविका और अर्थव्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। वैज्ञानिक प्रबंधन एवं चीड़ आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने लीसा विदोहन, चीड़ आधारित उत्पादों तथा एग्रो फॉरेस्ट्री को ग्रामीण विकास के लिए उपयोगी बताते हुए स्थानीय युवाओं एवं महिला समूहों की सहभागिता पर बल दिया। डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव ने कहा कि मध्य हिमालयी क्षेत्र में चीड़ आजीविका और

पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। लीसा विदोहन के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा इसे वैज्ञानिक तरीके से संचालित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों एवं स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग, सुमधुर एवं प्रेरणादायक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया तथा जन-जागरुकता के संदेश को प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंचाया। कार्यक्रम के माध्यम से लीसा विदोहन, वनाग्नि रोकथाम एवं वन संरक्षण के प्रति व्यापक जन-जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा संजय गुसाई, कनिष्ठ प्रमुख पोखड़ा संजय जोशी, जिला पंचायत सदस्य डोभ अनुज कुमार, जिला पंचायत सदस्य पोखड़ा बलवंत सिंह नेगी, जिला पंचायत सदस्य कालों भारत सिंह रावत, एसडीओ आयशा बिष्ट, एसडीओ सिविल एवं सोयम लक्की शाह, प्रशिक्षु आईएफएस विनीत कुमार, रेंजर पौड़ी प्रभाग नक्षत्र लव शाह, सेवानिवृत्त डीन सोलन वि.वि. डॉ. कुलवंत शर्मा, सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समूहों की महिलाएं एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

बहुउद्देश्यीय शिविर में ग्रामीणों ने बढ़चढ़ कर किया प्रतिभाग

पथ प्रवाह, पौड़ी। मुख्यमंत्री के निर्देशन में चल रहे 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के तहत विकासखंड पौड़ी की न्याय पंचायत चरधार के पंचायत भवन कंडी में बहुउद्देश्यीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने बढ़चढ़ प्रतिभाग कर अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी।

शिविर की अध्यक्षता एसडीओ वन आयशा बिष्ट ने की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि योजनाओं का लाभ गांव स्तर पर ही उपलब्ध हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ तत्काल उपलब्ध कराया जाए।

नोडल अधिकारी एवं तहसीलदार दीवान सिंह राणा ने बताया कि शिविर में कुल 30 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि शिविर में 164 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा

स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में लगभग 515 ग्रामीणों ने प्रतिभाग कर अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा 20 लाभार्थियों के प्रमाण पत्र भी बनाए गये। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य ममता नेगी, ग्राम प्रधान कंडी सुरेश लाल, प्रभारी खंड विकास अधिकारी दिनेश नेगी, एबीडीओ धनपाल सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित थे।

मुनीष सैनी का स्वागत करने उमड़ा जनसैलाब, विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर व्यापक जनसंपर्क

पथ प्रवाह, हरिद्वार

पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में 25 फरवरी को आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान पूर्व भाजपा प्रत्याशी और सह प्रभारी ओबीसी मोर्चा मुनीश सैनी ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। जनसंपर्क यात्रा के दौरान क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला और हजारों लोगों ने कार्यक्रम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत भाजपा नेता मुनीश सैनी ने ग्राम रांघडवाला, मेवड़ खुर्द उर्फ नांगल, टांडा, इमली खेड़ा, माजरी, गुम्मावाला, मेहवड़ कलां तथा मोहम्मदपुर पांडा सहित अनेक गांवों का दौरा किया। प्रत्येक गांव में स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया और सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का विश्वास दिलाया। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और सामाजिक प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही।

अपने संबोधन में मुनीश सैनी ने कहा कि ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज को एकजुट करने का कार्य करते हैं तथा हमारी परंपराओं और संस्कृति को सुदृढ़ बनाते हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की कि 25 फरवरी को आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में अपने परिवार और साथियों सहित अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं।

जनसंपर्क के दौरान उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, युवाओं को रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने तथा मूलभूत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का प्रेम और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी विश्वास के साथ वे क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

इस अवसर पर पंकज पाल, अनिल पाल, मोनू सैनी, मंडल अध्यक्ष गौरव मोहन सैनी, अंकुर सैनी, पवन (सभासद), अभिनव प्रताप, पंकज सैनी (महामंत्री), कुलवीर, राजेंद्र, प्रमोद, सुशील, शिव प्रसाद, हेमंत, प्रवीण सैनी, मोनू शर्मा, मनीष पाल, बिट्टू, शुभम सैनी, अजय सैनी, देवेंद्र सिंह, गंगा सैनी, प्रताप सिंह, अनिल कुमार, प्रीतम पाल, रजत पाल, राजेंद्र सिंह, शौर्य, कुलजीत, विपिन पाल, कर्मचंद, रितिक, धर्मपाल, राजकुमार, सोमपाल, मांगेराम, प्रमोद सैनी (मास्टर जी), अश्वनी सैनी, कंवर पाल सैनी, संजय सैनी, पवन रोड, यशवीर सहित अनेक कार्यकर्ता और सहयोगी उपस्थित रहे।

जनसंपर्क यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने यह संकेत दिया कि पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन को लेकर व्यापक उत्साह है और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। आयोजकों ने विश्वास व्यक्त किया कि 25 फरवरी को आयोजित होने वाला विराट हिंदू सम्मेलन अभूतपूर्व और सफल आयोजन सिद्ध होगा।

एक नजर

बोर्ड परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए 8 मुन्ना भाई

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां एक परीक्षा केंद्र पर हाईस्कूल के पेपर में असली परीक्षार्थियों के स्थान पर आठ दूसरे छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे थे। हालांकि इनमें से एक परीक्षार्थी मामला पकड़ में आने के बाद चकमा देकर मौके से फरार हो गया। अन्य सात से पूछताछ के बाद फर्जीवाड़े का पूरा सच सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पकड़े गए सात छात्र–छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई की है। घटना ने शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में यह बड़ा फर्जीवाड़ा हाईस्कूल हिंदी के पेपर में सामने आया है। आरोपी हरिद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर केंद्र पर एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। कक्ष निरीक्षक को शक हुआ तो उनके एडमिट कार्ड की गहनता से जांच की गई, जिसमें एक दो नहीं चार छात्र और चार छात्राएं बेनकाब हुई। सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने स्वीकारा कि वे किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने आए हैं। जिसके बाद यह सूचना उच्चधिकारियों और पुलिस को दी गई। सभी परीक्षार्थी प्राइवेट श्रेणी के हैं। सभी संदिग्धों की उत्तर पुस्तिकाएं जब्त कर सील कर गोपनीय अनुभाग को भेजी गई हैं। पुलिस ने फर्जीवाड़े के नेटवर्क की जांच शुरू करते हुए स्कूल और बाहरी कनेक्शन खंगालने शुरू कर दिये हैं। पुलिस के अनुसार, राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर में सावित्री शिक्षा सदन रावली महदूद के छात्र-छात्राओं का परीक्षा केंद्र है। बताया जा रहा है कि इस केंद्र पर हिंदी परीक्षा के पेपर में 13 परीक्षार्थी सम्मिलित होने थे, जिनमें से 10 उपस्थित हुए और तीन अनुपस्थित थे। इस मामले में कोतवाली रानीपुर प्रभारी आशुतोष राणा का कहना है, एक परीक्षार्थी मौके से फरार हो गया था, फिलहाल सात को प्रारंभिक जांच में धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस देकर उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन प्रधानाचार्य की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में स्कूल की भूमिका भी जांची जाएगी। सूत्रों के अनुसार प्रथम दृष्टया पूछताछ में दो संदिग्धों के नाम प्रकाश में आए हैं, इनसें पूछताछ के बाद पूरा खुलासा हो सकेगा।

एसडीएम ने कटहरा बाजार में जब्त की 06 कुंतल प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग

पथ प्रवाह, हरिद्वार। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनपद में अनाधिकृत प्लास्टिक की बिक्री एवं उपयोग करने वाले पर जुर्माना लगाने हेतु जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विगत दिनों आदेश निर्गत किया गया था। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी हरिद्वार राजस्व टीम एवं पुलिस बल के साथ ज्वालापुर कटहरा बाजार स्थित एवरग्रीन पॉलिपैक के दुकान पर छापेमारी की कार्यवाही की गई। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने अवगत कराया है कि निरीक्षण के दौरान एवरग्रीन पॉलिपैक की दुकान से अनाधिकृत एवं बैन पॉलीथिन के बैग बरामद किए गए,जो कि 06 कुंटल पॉलीथिन के बैग थे,जिन्हें जब्त किया गया। उन्होंने अवगत कराया कि अनधिकृत बैन पॉलीथिन के बैग का भंडारण एवं विक्रय करने पर संबंधित दुकानदार का एक लाख का चालान किया गया।उन्होंने कहा कि अनाधिकृत प्लास्टिक एवं बैग का भंडारण, विक्रय एवं उपयोग करने वालों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है,अनाधिकृत प्लास्टिक का उपयोग करने वाले पर नियमानुसार चालान की कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान ज्वालापुर कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक खेमेंद्र गंगवार, तहसीलदार सचिन कुमार सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल-2026 को भव्य बनाने की तैयारी तेज

पथ प्रवाह, पौड़ी।

सतपुली-बिलखेत में 26 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल-2026 को सफल एवं भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि तीन दिवसीय इस आयोजन को जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसे यादगार बनाया जाएगा। उन्होंने रेखीय विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल पर अपने-अपने विभागों के स्टॉल अनिवार्य रूप से स्थापित करें, ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक सीधे पहुंच सके। निर्देश दिए कि आयोजन के दौरान चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य टीम की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाए, जिससे स्थानीय लोग निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करा सकें। उन्होंने पर्यटन विभाग को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल के अतिरिक्त प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग, पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिकाधिक पर्यटक और स्थानीय लोग कार्यक्रम में सहभागिता कर सकें। साथ ही संस्कृति विभाग को सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे आयोजन में सांस्कृतिक रंग भी जुड़ सके।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिव मोहन शुक्ला, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल, जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक रणजीत सिंह नेगी, ग्रामोत्थान परियोजना प्रबंधक कुलदीप बिष्ट, जिला युवा कल्याण अधिकारी रविन्द्र फोनिया, जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार, जिला क्रीड़ा अधिकारी जयबीर सिंह रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

साकार होगा पौड़ी की विरासत को संजोने का सपना, जिलाधिकारी ने की समीक्षा

पथ प्रवाह, पौड़ी।

जनपद पौड़ी के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में हेरिटेज म्यूजियम की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान निर्माणदायी संस्था ने पीपीटी के माध्यम से प्रस्तावित स्वरूप और प्रदर्शित की जाने वाली सामग्रियों की जानकारी दी, जिस पर जिलाधिकारी ने म्यूजियम को जनपद की पहचान के अनुरूप विकसित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित म्यूजियम पौड़ी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को एक समग्र रूप में प्रस्तुत करेगा। उन्होंने निर्देशित किया कि इसमें पारंपरिक ढोल-दमाऊ, प्राचीन आभूषण एवं वेशभूषा, दुर्लभ छायाचित्र, हिमालय से जुड़ी थ्री-डी प्रस्तुतियां और अन्य महत्वपूर्ण धरोहरों को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए, जिससे आगंतुकों को जनपद की विरासत का वास्तविक अनुभव हो सके।

बैठक में प्रस्तावित हेरिटेज म्यूजियम की अवधारणा को और अधिक समृद्ध एवं आकर्षक बनाने के उद्देश्य से इसकी विभिन्न थीम आधारित दीर्घाओं (हॉल) पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि म्यूजियम में 'विरासत भूमि हॉल' के माध्यम से जनपद के ऐतिहासिक विकास, प्राचीन सभ्यता और महत्वपूर्ण पड़ावों को प्रदर्शित किया जाएगा, वहीं 'वीर भूमि हॉल' में वीरभूमि पौड़ी के शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं सैन्य परंपरा से जुड़े गौरवशाली योगदान को सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाएगा। 'लोक संस्कृति हॉल' में जनपद की समृद्ध लोक परंपराओं, पारंपरिक वाद्य यंत्रों, वेशभूषा, आभूषण, लोक कला एवं रीति-रिवाजों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि 'तपोभूमि हॉल' में जनपद के प्राचीन मंदिरों, आध्यात्मिक स्थलों, ऋषि-मुनियों की तपस्थली और धार्मिक महत्व को दर्शाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 'प्राकृतिक हॉल' में हिमालय की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, नदियों, वन संपदा और प्राकृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com